International Journal of Engineering, Management and Humanities (IJEMH)
Volume 3, Issue 1, pp: 248-251 www.ijemh.com

शिक्षा के व्यावसायीकरण पाठ्यक्रम का अध्ययनः उद्देश्य एवं चुनौतियॉ

शशि कुमारी तिर्कि, शोधकर्ता, तथा शुभ्रा ठाकुर, सह प्राध्यापक
AISECT UNIVERSITY

Date of Submission: 07-03-2022 Date of Acceptance: 23-03-2022

सार :
हमारे देश में व्यवसायिक शिक्षा का प्रचलन अति प्रचीनकाल से ही रहा है। उसका स्वरुप आधुनिक समय में विकसित प्राविधिक और व्यावसायिक शिक्षा सें सर्वथा भिन्न और आश्चर्यचकित करने वाला है।शिक्षा में व्यवसायीकरण का बहुत महत्व है। यह न सिर्फ देश के आर्थिक विकास तथा बेरोजगारी की समस्या दूर कर सकता है। बल्कि लोगों के बौद्धिक क्षमता, योग्यता, उत्पादता एवं सामाजिक समायोजन के विकास में भी सहायक सिद्ध होगा। अतः शिक्षा में व्यवसायीकरण या माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण का अर्थ है कि कोई ऐसा प्रशिक्षण शिक्षा के माध्यम से देना जिससे विद्यार्थी अपने जीवन में कोई न कोई व्यवसाय करके अपनी आजीविका कमा सकें। उच्च माध्यमिक स्तर पर व्यवसाय शिक्षा देश की समस्याओं के समाधान में एक अहम् भूमिका अदा करती है।सन 1986 में व्यवसायिक शिक्षा की मन्द गति के निम्नलिखित कारण बताएँ गये है :–मांग तथा विवरण में असमांगिकता, समाज की विचारधारा को स्वीकार करने में अनिच्छा, व्यवसायिक शिक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद की बेरोजगारी आदि।1952–53 के मुदालियर आयोग तथा 1964–66 के कोठारी आयोग ने यह संस्तुतियाँ दी थीं कि शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जाये, कम से कम माध्यमिक शिक्षा स्तर को पूर्णतः व्यवसायीकृत करने की संस्तुतियाँ प्रस्तुत की थीं। इन्होंने सामान्य शिक्षा के साथ–साथ व्यवसायों की शिक्षा देकर कार्यानुभव को बढ़ाने की बात कहीं थी।

Keywords: *व्यवसायीकरण, बेरोजगारी, समायोजन*

परिचय :–

''व्यवसाय'' शब्द जीविकोपार्जन के लिए अपनाये जाने वाले कारोबार के अर्थ में है तथा शिक्षा–संबंधित व्यवसाय के प्रशिक्षण युक्त सीखने से है। तात्पर्य–व्यावसायिक शिक्षा वह शिक्षा है जो व्यवसाय संचालन संबंधी जानकारी प्रदान करती है। व्यावसायिक शिक्षा कामगारों को दी जाने वाली शिक्षा या प्रशिक्षण है इसकी उत्पत्ति कार्य प्रशिक्षण अथवा कार्य अभ्यास से मानी जाती है। इसी प्रकार की शिक्षा या प्रशिक्षण जिसमें कामगार भाग लेता है को व्यावसायिक शिक्षा कहते हैं। हमारे देश में व्यवसायिक शिक्षा का प्रचलन अति प्रचीनकाल से ही रहा है।

उसका स्वरुप आधुनिक समय में विकसित प्राविधिक और व्यावसायिक शिक्षा सें सर्वथा भिन्न और आश्चर्यचकित करने वाला है। ऐसे संकेत मिलते हैं कि प्राचीन काल में हमारा देश व्यावसायिक शिक्षा क्षेत्र में अपने चरमगोत्कर्ष पर था। उस तरह का पहला निश्चित प्रमाण हमें सैन्धव सभ्यता सें हमें प्राप्त होता है। यहाँ की नगर निर्माण योजना, गोदामों, और भंडारगृहों के निर्माण रत्न, धातु, कृषि, शिल्प तथा अन्य व्यवसायों के अलावा जलपोत निर्माण तथा अन्य देशों से व्यापार आदि के ठोस प्रमाण उधोग व्यवसायों के पूर्ण विकास का परिचय देती है। शिक्षा में व्यवसायीकरण का बहुत महत्व है। यह न सिर्फ देश के आर्थिक विकास तथा बेरोजगारी की समस्या दूर कर सकता है। बल्कि लोगों के बौद्धिक क्षमता, योग्यता, उत्पादता एवं सामाजिक समायोजन के विकास में भी सहायक सिद्ध होगा(मंजु मिश्रा 2007)। भारत की पुरानी शिक्षा पद्धति 10+2+3 में विद्यार्थियों के सामने दो मार्ग है। एक मार्ग व्यवसायिक एवं औद्योगिक शिक्षा की ओर तथा दूसरा एकेडैमिक शिक्षा। यह विद्यार्थियों की रूचि, अभिरूचि, बौद्धिक स्तर एवं कार्यक्षमता के अुनसार है।

सन 1986 में व्यवसायिक शिक्षा की मन्द गति के निम्नलिखित कारण बताएँ गये है :–मांग तथा विवरण मे असमांगिकता, समाज की विचारधारा को स्वीकार करने में अनिच्छा, व्यवसायिक शिक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद की बेरोजगारी आदि। शिक्षा में व्यवसायिक निर्देशन की अहम भूमिका होती है। राष्ट्रीय व्यवसायिक निर्देशन संघ ;ने 1937 में कहा है कि – व्यवसायिक निर्देशन किसी व्यक्ति को व्यवसाय के चयन,

तैयारी, प्रवेश तथा उसमें उन्नति करने में सहायता देने की प्रक्रिया है। माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों में भावनात्मक तथा व्यवसायिक चयन में गलतियों की संभावना होती है। अतः व्यवसायिक निर्देशन के द्वारा भावों तथा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का हल किया जाता है।

अत: शिक्षा में व्यवसायीकरण या माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण का अर्थ है कि कोई ऐसा प्रशिक्षण शिक्षा के माध्यम से देना जिससे विद्यार्थी अपने जीवन में कोई न कोई व्यवसाय करके अपनी आजीविका कमा सकें। उच्च माध्यमिक स्तर पर व्यवसाय शिक्षा देश की समस्याओं के समाधान में एक अहम् भूमिका अदा करती है। कोठारी आयोग के अनुसार माध्यमिक शिक्षा पर अधिक बल देना चाहिए। इसी आयोग का कथन है कि "हमारी यह कल्पना है कि भविष्य में स्कुली शिक्षा की प्रकृति सामान्य एवं व्यवसायिक शिक्षा के लाभदायक मिश्रण की ओर होगी। सामान्य शिक्षा में पूर्व व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा के कुछ तत्व सम्मिलित होंगे और इसी प्रकार व्यवसायिक शिक्षा में शिक्षा के कुछ तत्व सम्मिलित होंगे।

व्यवसायिक शिक्षा वह है जो लोगों को एक तकनीशियन या ट्रेडमैन के रूप में विभिन्न नौकरियों में काम करने के लिए तैयार करती है। व्यवसायिक शिक्षा माध्यमिक, आगे की शिक्षा या उच्च शिक्षा के स्तर पर हो सकती है। यदि हम भारत में उन्नति या रोजगार स्थापित करना चाहते हैं या भारत को विकसित करना चाहते हैं या सभी जाति, धर्म के लोगो को आगे देखना चाहते हैं या भारत को विकसित करना चाहते हैं तो हमें संकल्प लेना होगा कि कोई भी शिक्षा के बगैर अधूरा न रह जाए। क्योंकि शिक्षा वह है, जो हर इंसान को आगे बढ़ाएगी और रोजगार दिखाएगी।

"व्यवसाय परक शिक्षा व्यक्तियों को एक विशिष्ट कार्य के योग्य बनाती है, जिससे अपनी विशिष्ट सेवाओं के द्वारा समाज में विशिष्ट क्षमता का प्रदर्शन करता है।"
–जॉन डी. वी.

"व्यापक रूप मे ं व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत उस सब प्रकार की शिक्षा का` सम्मिलित किया जा सकता है, जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को जीविकोपार्जन के लिए प्रशिक्षण प्राप्त होता है।"
– सामाजिक विज्ञानों का विश्वकोश

शिक्षा के व्यवसायीकरण के लिए प्रयत्न

1952–53 के मुदालियर आयोग तथा 1964–66 के कोठारी आयोग ने यह संस्तुतियाँ दी थीं कि शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जाये, कम से कम माध्यमिक शिक्षा स्तर को पूर्णतः व्यवसायीकृत करने की संस्तुतियाँ प्रस्तुत की थीं। इन्हो ने सामान्य शिक्षा के साथ–साथ व्यवसायो की शिक्षा देकर कार्यानुभव का` बढ़ाने की बात कहीं थी। परन्तु किसी भी आयो गया समिति मे ं संस्तुतियो पर अमल करने का प्रयास नहीं किया गया। 1953 में कुछ बहुउद्देशीय विद्यालयों ;डनसजपचनतचवेम "बीववसेद्ध खोलने की योजना बनायी गयी थी, परन्तु धनाभाव में वह भी ठप्प हो गयी। राधाकृष्णन आयोग 1948–49 ने गाँवों में ग्रामीण विश्वविद्यालय ;त्नतंस न्दपअमतेपजपमेद्ध खोलने की योजना दी थी। उसे भी लागू नहीं किया। वर्धा शिक्षा–योजना के अन्तगत गाँधी जी ने बेसिक शिक्षा को कार्यान्वित करने की बात पर बार–बार बल दिया था। उसे भी सफल नहीं बनाया जा सका। इस प्रकार सरकार ने शिक्षा के व्यवसायीकरण के लिए सफल प्रयास नहीं किया।

भारत सरकार ने कुछ परियो जनाओ ;च्पसवज च्तवरमबजेद्ध का पॉयलट प्रोजेक्ट ;च्पसवज च्तवरमबजेद्ध के रूप मे चलाने का प्रयास किया। ऐसा कुछ अध्ययन समितियों ;जनकल ळतवनचेद्ध की सिफारियों के आधार पर किया गया। इनकी संस्तुति सम्बन्धी रिपोर्ट 1970 में प्रकाशित हुई थी। विशेषज्ञों की एक समिति ने इस रिपोर्ट का अध्ययन किया औ रकुछ जिलो ं और शिक्षा संस्थानों का ` इन परियोजनाओ के संचालन हे तु चु ना भी गया। परन्तु हुआ कुछ नहीं।

(अ) स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व किये गये प्रयत्न ;मीवितज डंकम ठमवितम प्दकमचमदकमदबमद्ध –1882 ई० में शिक्षा का भारतीय आयोग गठित हुआ। उसे सुझाव दिया कि स्कूल के पाठ्यक्रम में व्यावसायिक विषयों को भी रखा जाये। परन्तु ब्रिटिश सरकार ने इस पर कोई अमल नहीं किया।

1929 ई० में हरटॉग समिति ;भ्ंतजवह ब्वउउपजजममद्ध का गठन किया गया जिसने सुझाव दिया कि मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद विद्यार्थियों को माध्यमिक स्तर पर औद्योगिक विषय ;प्दकनेजतपंस "नइरमबजद्ध तथा वाणिज्य विषय ;ब्वउउमतबम "नइरमबजद्ध पढ़ाये जायँ। इस पर खुले दिल से अमल नहीं हुआ।

1936–37 में वर्धा शिक्षा–योजना बनायी गयी और निर्णय लिया गया कि बेसिक शिक्षा–योजना को कार्यान्वित किया जाये। अतः बेसिक स्कूल खोले गये और प्रयास किया गया कि किसी के 'शिल्प' ;ब्तंजिद्ध के माध्यम से अन्य विषयों का अध्ययन सह–सम्बन्धित ;ब्वततमसंजमकद्ध रूप में कराया जाये।

1937 में ब्रिटिश सरकार ने एबॉट वुड समिति ;।इइवज ॅववक ब्वउउपजजममद्ध गठित की जिसने सुझाव दिया कि भारत में बेरोजगारी दूर करने के लिए स्कूलों में व्यावसायिक विषय चलाये जायँ।

(ब) स्वतंत्र भारत में प्रयास ;मीवितज पद प्दकमचमदकमदज प्दकपंद्ध. स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में शैक्षिक सुधार लाने के लिए बहुत सी समितियों और आयोग बने जिन्हेंने स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा देने के सुझाव प्रस्तुत किये। जैसे –

1948–49 में राधा कृष्णन आयोग के सुझाव–1948–49 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता मे गठित हुआ। इसने संस्तुति दी थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ ग्रामीण विश्वविद्यालय ;त्नतंस न्दपअमतेपजपमेद्ध खोलो जाये जो गाँवों में कृषि से सम्बन्धित व्यवसायों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करें। साथ ही साथ उसने मेडिकल कॉलेज, इन्जीनियरिंग कॉलेज, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज खोलने तथा कानून की शिक्षा देने की भी बात की थी।

International Journal of Engineering, Management and Humanities (IJEMH)
Volume 3, Issue 1, pp: 248-251
www.ijemh.com

1952–53 के मुदालियर आयोग के सुझाव–1952–53 में माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं के सुधार हेतु सुझावों के लिए मुदालियर आयोग की स्थापना की गयी। इसके व्यवसायिक शिक्षा के संबंध में सुझाव इस प्रकार थे–

(1) बहुउद्देशयी माध्यमिक विद्यालय ;डनसजपचनतचवेम ैबीववसेद्ध खोले जाये। उनमें छात्र–छात्राओं की रूचियों, अभिरूचियों, और आवश्यकताओं के अनुकूल व्यावसायिक विषय पढ़ाये जाये। प्रचलित माध्यमिक स्कूलों को भी बहुउद्देशीय विद्यालयों में बदला जाये। सभी व्यवसायिक विषयों को सात समूहों ;ळतवनचेद्ध गठित किया जाये। सभी विद्यार्थियों के लिए आवश्यक हो कि वह अपनी रूचि के अनुकूल किसी भी समूह से एक व्यावसायिक विषय अवश्य पढ़े। प्रत्येक स्कूल में शैक्षिक निर्देशन ;म्कनबंजपवदंस ळनपकंदबमद्ध तथा व्यावसायिक निर्देशन ;टवबंजपवदंस ळनपकंदबमद्ध की व्यवस्था भी हो।

(2) प्रत्येक छात्र–छात्रा को उत्पादन ;च्तवकनबजपवदद्धका अवसर दिया जाये। पाठ्यक्रम बहुविकल्प वाला ;क्तपअम `गपिगकद्ध हो। इससे छात्र अपनी रूचि और क्षमता के शारीरिक श्रम वाले व्यवसाय को चुन सकेगा।

(3) छात्रों को 'कृषि' में सैद्धान्तिक और व्यवहारिक शिक्षा मिलें। इसके अन्तर्गत पशुपालन ;।दपउंस भ्नेइंदकतलद्ध पशुचिकित्सा विज्ञान ;टमजमतपदंतल ैबपमदबमद्ध मधुमक्खी पालन ;ठमम.ज्ञममचपदहद्ध आदि में प्रशिक्षण की व्यवस्था हो। ग्रामीण क्षेत्रों के बालकों के लिए ये पाठ्यक्रम बहुत उपयोगी माने गये।

(4) स्कूलों में तकनीकी शिक्षा ;ज्मबीदपबंस म्कनबंजपवदंसद्ध मिले। छात्र अपनी रूचि के किसी भी तकनीकी विषय को पढ़ सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। इस शिक्षा के लिए धन की पूर्ति करने की दृष्टि से औद्योगिक कर ;प्दकनेजतपंस जंगद्ध की व्यवस्था की जाये। केन्द्रीय सरकार प्रतिवर्ष राज्य सरकारों को आर्थिक सहायता दे और एक संघात्मक तकनीकी परिषद् ;थ्मकमतंस ज्मबीदपबंस ठवंतकद्ध स्थापित की जाये तो इस शिक्षा को चलायें

1964–66 के कोठारी आयोग के सुझाव–इस आयोग में माध्यमिकी शिक्षा स्तर पर कार्यानुभव ;ॅवता म्गचमतपमदबमद्ध की शिक्षा देकर शिक्षा के व्यवसायीकरण पर बल दिया। उसने इस शिक्षा को दो स्तरों पर देने की बात कही–

(अ) जूनियर माध्यमिक स्तर पर–जो विद्यार्थी मिडिल परीक्षा या जूनियर हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण कर लें उन्हें इण्डस्ट्रीयल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट ;प्ज्प्द्ध में प्रवेश दिया जाये। छात्रों की प्रवेश–आयु घटाकर 14 वर्ष कर दी जाये। इससे प्राथमिक शिक्षा प्राप्त बालक भी लाभ उठा सकेगा, जो बालक घर के काम में लगे रहते हैं। उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए अंशकालीन ;च्ंतज जपउमद्ध व्यवस्था की जाये। छात्र–छात्राओं को क्रमशः कृषि–उद्योग और गृह–विज्ञान ;भ्वउम ैबपमदबमद्ध में प्रशिक्षण मिले।

(ब) उच्चतर माध्यमिक स्तर पर–जो बालक माध्यमिक कक्षा पास कर लें उन्हें बहुधन्धी विद्यालयों ;च्वसलजमबीदपबंस प्देजपजनजपवदेद्ध में भर्ती करने की व्यवस्था की जाये। इन विद्यार्थियों के लिए यदि वे नियमित ;त्महनसंतद्ध रहकर शिक्षा न प्राप्त कर सकें, पत्राचार ;ब्वततमेचवदकमदबमद्ध और अंशकालीन ;च्ंतज जपउमद्ध व्यवस्था से विविध व्यवसायों की शिक्षा दी जाये। ये पाठ्यक्रम 3 माह से 6 माह तक के लिए हो सकते हैं।

पत्राचार और अंशकालीन व्यवस्था से व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए कुछ समितियों ;ैमचंतंजम ब्वउउपजजममेद्ध और उप समितियाँ ;ैनइ. ब्वउउपजजममेद्ध बनायी जाये जो शिक्षा विभाग के अंतर्गत हों। पहलें हमें विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यक मानव–शक्ति ;डंद च्वूमतद्ध का सर्वेक्षण करना चाहिए ताकि यह जाना जा सके कि अमुक क्षेत्र में कितने व्यक्ति और चाहिए। उनके ही व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाये। इस संबंध में उन औद्योगिक संस्थाओं ;थ्पतउेद्ध से परामर्श लिया जाये जो भविष्य में प्रशिक्षित व्यक्तियों की अपने यहाँ काम दे सकते हों।

व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा के लिए केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को आर्थिक सहायता दें। इसी प्रकार की आर्थिक सहायता से संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकांश माध्यमिक विद्यालय व्यवसायीकृत हो गये हैं।

कोठारी आयोग ने सुझाव दिया कि व्यावसायिक शिक्षा की सभी सुविधाएँ चलती रहें। प्रशिक्षार्थियों का अर्द्धकुशल ;ैमउप.ैापससमकद्ध और कुशल ;ैापससमकद्ध दो वर्गों में बाँटकर शिक्षा दी जाये। इन संस्थाओं की संख्या बढ़ायी जाये। निजी संस्थाओं को भी प्रोत्साहित किया जाये।हम अभिभावकों और छात्रों को व्यवसायिक शिक्षा पाने के लिए प्रेरित करें। व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम रोचक बनाये जाय। स्कूलों में शैक्षिक तथा व्यावसायिक शिक्षा निर्देशन ;ळनपकंदबमद्ध की स्थापना करें। जिसमें छात्रों को मनोवैज्ञानिक ढंग से निर्देशन मिल सके।

शिक्षा के व्यवसायीकरण के उद्येश्य

1. प्रत्येक व्यक्ति की रोजगार क्षमताओं को बढ़ाना और उनकी रूचि अनुसार उनको शिक्षा और रोजगार देना।
2. कुशल जनशक्ति की माँग और आपूर्ति के बीच अंतर को कम करना।
3. शिक्षा के सुअवसरों में विभिन्नता लाना।
4. विद्यार्थियों में आत्मविश्वास लाना।
5. निरूद्देष्य एवं रूचिविहीन उच्च शिक्षा प्राप्त विद्यार्थियों को विकल्प उपलब्ध कराना।
6. अधिक संख्या में स्वरोजगार आधारित पाठ्यक्रमों को तैयार करना।

निष्कर्ष–

शिक्षा प्राप्त करना हर बच्चे का अधिकार है इससे हम सभी सहमत हैं। शैक्षिक प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जो विद्यार्थियों मे बुनियादी क्षमताओं और कौशलों का विकास कर सके ताकि वह एक संतुलित जीवन जीने के लिए तैयार हो सकें और राष्ट्र के विकास की प्रक्रिया मे भागीदार बन सकें। ऐसा तभी सम्भव है जब विद्यार्थी सीखे गये सैद्धांतिक ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग भी कर सके। इसलिए शिक्षा को मजबूत व्यावसायिक आधार प्रदान करने की जरूरत है। व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था न केवल अलग संस्थाओं में की जानी चाहिए बल्कि स्कूली शिक्षा के हर स्तर की पाठ्यचर्चा से इसे अंतरंग रूप से जोड़ा जाना चाहिए। कुछ ऐसी ही संस्तुतियाँ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा–2005 में की गयी है।

–: सन्दर्भग्रन्थ–सूची :–

1. नयी शिक्षा नीति (1986) : गाइडेन्स और शिक्षा नीति (1986) उद्घृत सीताराम जायसवाल शिक्षा मे निर्देशन व परामर्श, विनोद पुस्तक मंदिर आगरा।
2. थॉमस एफ०डब्ल्यु० उद्घृत अभिषेक सिंह (2007) : व्यावसायिक वरीयता का एक अध्ययन पी–एच०डी० शिक्षा संकाय वी०ब०सिंह पू०वि०वि० जौनपुर।
3. वुड डिस्पैच (1854) : भारतीय शिक्षा की वर्तमान समस्यायें दिल्ली रिसर्च इन सोशल साइंसेज वाई०पी० अग्रवाल।
4. भारतीय विश्वविद्यालय आयोग (1902) : स्टडीज इन इंडियन एजूकेशन नयी दिल्ली आर्य बुक डिपो (1968) वी०ए० माथुर।
5. शिक्षा नीति (1913) : प्रॉब्लम्स ऑफ हायर एजूकेशन इन इंडिया बम्बई पापुलर प्रकाशन (1977) के०एल० जोशी।
6. कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग (1917–19) : थाट्स ऑन यूनिवर्सिटी एज्यूकेशन।
7. मिश्र राजकुमारी– "गांधी की बुनियादी शिक्षा", शिविरा पत्रिका, नव, (2002), पृष्ठ–31, 104
8. त्यागी औकांर सिंह, त्यागी एम०पी० सिंह– "विद्यालय प्रबंधन एवं शैक्षिक नवाचार" (2002), पृष्ठ सं०–251
9. वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (1996–97) प्राथमिकी एवं माध्यमिक शिक्षा, विभाग, राजस्थान, पृष्ठ 43–47
10. वर्मा एवं उपाध्याय–"शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन"–विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा (1982), पृष्ठ 78–79